

an>

title: Regarding sugar policy.

**श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह शुगर इंडस्ट्री द्वारा किसानों को शुगरदान करने की एफआरपी और किसानों से जुड़ा हुआ विषय है, 26 अप्रैल, 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्डिनेंस पास किया है, एक गजट प्रसारित किया है, जिसमें स्टॉक लिमिट को घोषित किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल को 10 हजार टन तथा अन्य राज्यों के लिए 50 हजार टन तक की सीमा तय की गयी है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अगले साल देश में शुगर की प्रोडक्शन कम हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है क्योंकि पिछले साल का स्टॉक 90 लाख टन है। इस साल का प्रोडक्शन 260 लाख टन हुआ है, कुल मिलाकर 350 लाख टन था। इसमें से सिर्फ 15 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है और 335 लाख टन डोमेस्टिक यूज होता है और अभी भी 90 लाख टन स्टॉक हो सकता है। अगले साल संभावना है कि 240 लाख टन प्रोडक्शन होगा इसलिए यह वजह ठीक नहीं लग रही है। स्टॉक लिमिट के निर्णय से बाजार में शुगर के रेट 400 रुपए विवंटल तक गिरावट आ गई है। इस निर्णय से न शुगर इंडस्ट्री और न ही ग्राहक को फायदा नहीं हो रहा है, इससे केवल स्टोरियों को फायदा हो रहा है जो शुगर स्टॉक करते हैं, 30 रुपए प्रति किलो शुगर लेते हैं और बाजार में 40-45 रुपए किलो बेतते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो साल में 1900 रुपए रेट शुगर का था, इस कारण एफआरपी देने में शुगर फैक्ट्रियों को दिक्कत आ रही थी। इन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर एफआरपी अदा की है। दो साल में बैंक प्रति टन 200 रुपए कट करके पैसा दे रही है, इस वजह से इस साल भी शुगर फैक्ट्रियां एफआरपी देने में नाकामयाब हैं। इससे किसानों और फैक्ट्रियों के लिए मुश्किल हो रही है।

प्यूवर ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। पिछले साल 16,000 करोड़ एज़म्पशन प्यूवर ट्रेडिंग में दिखाया गया था जबकि प्रत्यक्ष रूप में 16 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी। बाजार में सटोरिए आर्टिफिशियल तेजी का निर्माण करते हैं जिसके कारण डायरेक्ट सेल प्रभावित होती है। जब तक यह रेट 3500 रुपए नहीं होगा तब तक शुगर फैक्ट्रियां एफआरपी नहीं दे पाएंगी। शुगर प्रोडक्शन में से सिर्फ 25 परसेंट शुगर खाने के लिए यूज होती है बाकी 75 परसेंट शुगर इंडस्ट्री को जाती है, चॉकलेट, बिस्कुट के लिए यूज होती है। हम लोग जो खाते हैं अगर उसका रेट 30 रुपए और इंडस्ट्री को जो शुगर जाती है, उसका रेट 60 रुपए कर दिया जाए तो भी शुगर फैक्ट्रियों को फायदा होगा। पिछले साल स्टील इंडस्ट्री रिसेशन में आई थी, तब सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, लोन 25 साल के लिए रिशेड्यूलिंग करके दिया था। इसी तरह शुगर फैक्ट्रियों का लोन 25 साल के लिए रिशेड्यूल करके दिया जाए और तीन साल का मोरेटोरियम पीरीयड दिया जाए।

सरकार एक्सपोर्ट बंद का विचार कर रही है, यह बंद नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि कम से कम 40 लाख टन एक्सपोर्ट होना चाहिए। रंगनाथन कमेटी ने सीएसीपी एफआरपी देने के लिए डिमांड किया था, उसकी रिकमेंडेशन सरकार को मान लेनी चाहिए, 70-30 का रेश्यो तय किया था। 30 परसेंट इंडस्ट्री के लिए और 70 परसेंट किसानों के लिए तय किया था, अगर यह रेश्यो कर दिया जाएगा तो यह इंडस्ट्री पुनर्जीवित हो सकती है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन सरकार से करना चाहता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री ए.टी. नाना पाटिल, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।